Vol 5, Issue 3, March 2025 www.ijesti.com E-ISSN: 2582-9734
International Journal of Engineering, Science, Technology and Innovation (IJESTI)

कौशल प्रशिक्षण और महिला आर्थिक स्वायत्तता: झारखंड के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन

Bharti Kumari
Research Scholar, Department of Education, Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand.

सार

यह शोध झारखंड के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 420 महिलाओं के सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं फोकस समूह चर्चा के आधार पर अध्ययन से पता चला कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की आय, निर्णय-क्षमता, उद्यमिता, संसाधनों पर नियंत्रण और सामाजिक सहभागिता में अप्रशिक्षित महिलाओं की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण का प्रभाव मुख्यतः आय-वृद्धि और सूक्ष्म-उद्यमिता में दिखाई देता है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में इसका प्रभाव आत्म-विश्वास, सामाजिक सहभागिता और वित्तीय जागरूकता में अधिक पाया गया। t-test, ANOVA और Regression विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि कौशल प्रशिक्षण आर्थिक स्वायत्तता का महत्वपूर्ण निर्धारक है। अध्ययन स्थानीय संसाधनों, संस्कृति-संवेदनशील प्रशिक्षण और SHG-आधारित मॉडल को सशक्तिकरण का प्रभावी साधन मानता है।

Keywords: आर्थिक स्वायत्तता, आदिवासी महिलाएँ, ग्रामीण महिलाएँ, उद्यमिता, निर्णय-क्षमता, झारखंड।

1. परिचय

महिला आर्थिक स्वायत्तता को सतत विकास, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन का आवश्यक घटक माना जाता है। *UN-Women (2023)* के अनुसार, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सीधे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन नियंत्रण और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी होती है। झारखंड में अधिकांश महिलाएँ कृषि, वनोपज, तसर-रेशम, हस्तशिल्प और दिहाड़ी श्रम पर निर्भर हैं, जिससे उनकी आय अनियमित और सीमित रहती है (*Jharkhand Economic Survey, 2023*)।

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण मुख्यत: सिलाई-कढ़ाई, खाद्य-प्रसंस्करण, डिजिटल कौशल और लघु उद्यमिता पर केंद्रित है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में तसर-रेशम, लाह-प्रसंस्करण, बांस-उत्पाद और आजीविका-आधारित प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रभावी रहा है। कई अध्ययनों में कौशल प्रशिक्षण को आय-वृद्धि, निर्णय-क्षमता और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना गया है (कौशल, 2016; कुमारी, 2018), किंतु ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन अभी सीमित है। यह शोध इसी ज्ञान-अंतर को भरने का प्रयास है। अनेक अध्ययनों ने कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाया है। शर्मा एवं सिंह (2015) ने ग्रामीण महिलाओं की आय में प्रशिक्षण के कारण 30-50% वृद्धि पाई। अहमद (2017) ने SHG-आधारित कौशल प्रशिक्षण को आदिवासी महिलाओं में उद्यमिता के बढ़ते रुझान से जोड़ा। कुमारी (2018) ने दिखाया कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की औसत आय अप्रशिक्षित महिलाओं से अधिक होती है। जोशी (2020) ने बताया कि वित्तीय

साक्षरता व कौशल प्रशिक्षण का संयुक्त प्रभाव महिलाओं की निर्णय-क्षमता और संसाधनों पर नियंत्रण को बढ़ाता है। नायर एवं मुखर्जी (2022) ने तसर प्रशिक्षण को आदिवासी क्षेत्र में स्थिर आजीविका का स्रोत माना। *MSDE (2022)* रिपोर्ट में उल्लेख है कि प्रशिक्षण महिला उद्‌यमिता और सूक्ष्म व्यवसायों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के प्रभावों का संरचनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक तुलना पर केंद्रित अध्ययन सीमित है—और यही इस शोध की विशेष प्रासंगिकता स्थापित करता है।

3. शोध उद्‌देश्य

यह अध्ययन इस उद्‌देश्य से डिजाइन किया गया है कि झारखंड के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर कौशल प्रशिक्षण के वास्तविक प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके। शोध का लक्ष्य न केवल दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना है, बल्कि कौशल प्रशिक्षण से उत्पन्न हुए आय, उद्‌यमिता और निर्णय-क्षमता के अंतर को भी तुलनात्मक रूप से विश्लेषित करना है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन प्रशिक्षण स्वीकारने में आने वाली बाधाओं व समर्थक कारकों की पहचान करते हुए क्षेत्र-विशेष उपयुक्त नीतिगत सुझाव विकसित करने का प्रयास करता है।

1. ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता की वर्तमान स्थिति का .
2. दोनों क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के प्रभावों की तुलना करना।
3. प्रशिक्षण का महिलाओं की आय, उद्‌यमिता और निर्णय-क्षमता पर प्रभाव मापना।
4. प्रशिक्षण ग्रहण करने की बाधाएँ और सक्षम कारकों की पहचान।
5. क्षेत्र-विशेष आधारित नीति सुझाव प्रस्तुत करना।

4. परिकल्पनाएँ

इस अध्ययन में प्रस्तुत परिकल्पनाएँ इस धारणा पर आधारित हैं कि कौशल प्रशिक्षण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता, आय-वृद्‌धि, उद्‌यमिता तथा निर्णय-क्षमता में सार्थक परिवर्तन लाता है। इन परिकल्पनाओं का उद्‌देश्य ग्रामीण और आदिवासी दोनों क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के प्रभावों की तुलनात्मक जाँच करना तथा यह समझना है कि क्या प्रशिक्षण वास्तव में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक परिवेश को प्रभावित करता है।

H1: कौशल प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता अप्रशिक्षित महिलाओं से अधिक है।

H2: ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं पर कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव में सार्थक अंतर है।

H3: प्रशिक्षण उद्‌यमिता अपनाने की संभावना को बढ़ाता है।

H4: कौशल प्रशिक्षण और निर्णय-क्षमता के बीच सकारात्मक संबंध है।

5. शोध पद्धति

इस अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक शोध-डिज़ाइन अपनाया गया, ताकि ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता पर कौशल प्रशिक्षण के प्रभावों को बहु-दृष्टिकोण से समझा जा सके। अध्ययन क्षेत्र के रूप में झारखंड के प्रतिनिधिक जिलों का चयन किया गया—ग्रामीण क्षेत्र के लिए हजारीबाग और लोहरदगा, तथा आदिवासी क्षेत्र के लिए खूंटी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम। कुल 420 महिलाओं का नमूना निर्धारित किया गया, जिसमें 210 ग्रामीण और 210 आदिवासी महिलाएँ शामिल थीं; नमूना चयन बहु-चरणीय नमूना विधि के माध्यम से किया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक विविधता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। डेटा संग्रह के लिए लिकर्ट-स्केल आधारित संरचित प्रश्नावली, अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार एवं फोकस समूह चर्चा (FGDs) का उपयोग किया गया, जिससे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु Mean, Standard Deviation (SD), t-test, ANOVA, Pearson Correlation तथा Regression जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक स्वायत्तता के विभिन्न आयामों के बीच संबंधों और अंतर को वैज्ञानिक रूप से मापा जा सके।

6. डेटा विश्लेषण

6.1 आय में परिवर्तन

समूह	*प्रशिक्षित (₹)*	*अप्रशिक्षित (₹)*
ग्रामीण महिलाएँ	13,200	9,500
आदिवासी महिलाएँ	11,800	8,200

अध्ययन में पाया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की औसत मासिक आय ₹13,200 है, जबकि अप्रशिक्षित महिलाओं की आय ₹9,500 पाई गई; t-test मान 4.98 ($p < .01$) होने से यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित महिलाओं (₹11,800) और अप्रशिक्षित महिलाओं (₹8,200) के बीच आय-अंतर स्पष्ट है, जहाँ t-test = 4.52 ($p < .01$) प्राप्त हुआ। ये परिणाम दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण महिलाओं की आय-सृजन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, जो **कुमारी (2018)** और **MSDE रिपोर्ट (2022)** के निष्कर्षों से भी मेल खाता है कि कौशल शिक्षा आय-वृद्धि का प्रभावी साधन है।

6.2 उद्यमिता क्षमता

समूह	*उद्यम शुरू करने वाली महिलाएँ (%)*
ग्रामीण प्रशिक्षित	41%
आदिवासी प्रशिक्षित	34%
ग्रामीण अप्रशिक्षित	18%
आदिवासी अप्रशिक्षित	14%

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण महिलाओं में 41% तथा आदिवासी महिलाओं में 34% ने स्वयं का उद्यम प्रारंभ किया, जबकि अप्रशिक्षित समूहों में यह अनुपात क्रमशः 18% और 14% ही पाया गया। प्रतिगमन विश्लेषण ($\beta = .39$, $p < .01$) यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण महिला उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण और सशक्त पूर्वानुमानक है। ये निष्कर्ष **अहमद (2017)** के अध्ययन से मेल खाते हैं, जिसमें SHG-आधारित प्रशिक्षण को उद्यमिता वृद्धि का प्रमुख कारक बताया गया था। इसी प्रकार **MSDE (2022)** रिपोर्ट भी संकेत करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं में व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं।

6.3 निर्णय-क्षमता

निर्णय प्रकार	***ग्रामीण प्रशिक्षित***	***आदिवासी प्रशिक्षित***
वित्तीय निर्णय	68%	59%
घरेलू खरीद	73%	62%
बच्चों की शिक्षा/स्वास्थ्य	58%	54%

अध्ययन से पता चलता है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की निर्णय-क्षमता अधिक सुदृढ़ है– वित्तीय निर्णयों में 68%, घरेलू खरीद से जुड़े निर्णयों में 73% और बच्चों की शिक्षा/स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में 58% सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित महिलाओं की निर्णय-क्षमता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई पाई गई (59%, 62% और 54% क्रमशः)। सहसंबंध विश्लेषण ($r = .57$, $p < .01$) यह दर्शाता है कि कौशल प्रशिक्षण और निर्णय-क्षमता के बीच मध्यम से उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध मौजूद है। यह निष्कर्ष **जोशी (2020)** के अध्ययन से भी मेल खाता है, जिसमें वित्तीय साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण को महिलाओं की निर्णय-क्षमता में वृद्धि का प्रमुख कारक बताया गया था।

1. प्रशिक्षण ने ग्रामीण महिलाओं की आय में औसतन 38% और आदिवासी महिलाओं में 32% वृद्धि की।
2. ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता का प्रभाव अधिक पाया गया, जबकि आदिवासी महिलाओं में सामाजिक-आत्मविश्वास व निर्णय-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
3. SHG-आधारित मॉडल प्रशिक्षित महिलाओं के लिए सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ।
4. डिजिटल कौशल ने दोनों क्षेत्रों में बाज़ार-प्रवेश और आईटी आधारित अवसरों को बढ़ाया।

परिणाम दर्शाते हैं कि कौशल प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है, किंतु प्रभाव की प्रकृति भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण आय-वृद्धि और उद्यम सृजन पर अधिक केंद्रित है। इसके विपरीत, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का प्रभाव आत्म-विश्वास, सामाजिक सहभागिता और वित्तीय व्यवहारिकता पर अधिक स्पष्ट है। सांस्कृतिक कारक, संसाधन उपलब्धता और SHG नेटवर्क इन अंतर का कारण हैं – यह अहमद (2017) व नायर एवं मुखर्जी (2022) के निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

7. नीतिगत सुझाव

कौशल प्रशिक्षण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किन्तु इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाने हेतु नीतिगत स्तर पर संरचित एवं क्षेत्र-विशेष आधारित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। प्रस्तुत नीतिगत सुझाव इस उद्देश्य से तैयार किए गए हैं कि प्रशिक्षण केवल कौशल-विकास तक सीमित न रहकर महिलाओं को स्थायी आय, उद्यमिता, बाज़ार-संपर्क और सामाजिक नेतृत्व के अवसर भी प्रदान करे।

- क्षेत्र-विशेष आधारित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार-संपर्क, ब्रांडिंग और उद्यमिता समर्थन बढ़ाया जाए।
- आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक-आधारित प्रशिक्षण, स्थानीय भाषा में मॉड्यूल और मेंटरशिप मॉडल लागू हों।
- प्रशिक्षण-पश्चात वित्तीय सहायता और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की व्यवस्था की जाए।
- SHG-JSLPS मॉडल को राज्यभर में विस्तारित किया जाए।

8. निष्कर्ष

इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कौशल प्रशिक्षण झारखंड के ग्रामीण एवं आदिवासी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है, यद्यपि प्रभाव की प्रकृति दोनों क्षेत्रों में भिन्न है। ग्रामीण महिलाओं में प्रशिक्षण के बाद आय-वृद्धि, उद्यमिता अपनाने की प्रवृत्ति और बाज़ार-संपर्क अधिक सुदृढ़ हुए, जबकि आदिवासी महिलाओं में आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता, वित्तीय निर्णय-क्षमता और सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। सांख्यिकीय विश्लेषणों–t-test, Regression और Correlation–ने यह पुष्टि की कि कौशल प्रशिक्षण आर्थिक स्वायत्तता का महत्वपूर्ण पूर्वानुमानक है। कुल मिलाकर, कौशल शिक्षा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को गति देती है और क्षेत्र-विशेष आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

9. संदर्भ

- अहमद, एस. (2017). आदिवासी महिलाओं में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता का विश्लेषण। *भारतीय सामाजिक विकास पत्रिका*, 12(3), 45-58।
- कुमारी, पी. (2018). व्यावसायिक शिक्षा का महिलाओं की आय पर प्रभाव: एक क्षेत्रीय अध्ययन। *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट*, 14(1), 52-63।
- कौशल, आर. (2016). ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में कौशल प्रशिक्षण की भूमिका। *महिला अध्ययन पत्रिका*, 8(2), 30-41।
- शर्मा, एम., एवं सिंह, ए. (2015). ग्रामीण महिलाओं की आय-वृद्धि में कौशल प्रशिक्षण का योगदान। *महिला विकास अंतरराष्ट्रीय जर्नल*, 6(1), 25-36।

- जोशी, आर. (2020). वित्तीय साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण का महिलाओं की निर्णय-क्षमता पर प्रभाव। *वित्त एवं समाज पत्रिका*, 7(1), 15-29।
- मिश्रा, डी. (2021). कोविड-19 के बाद डिजिटल कौशल और ग्रामीण महिला उद्यमिता। *ग्रामीण विकास शोध पत्रिका*, 18(4), 65-79।
- नायर, वी., एवं मुखर्जी, एस. (2022). तसर-रेशम प्रशिक्षण और आदिवासी महिलाओं की आजीविका स्थिरता: पूर्वी भारत का अध्ययन। *पूर्व भारत विकास जर्नल*, 5(3), 98-112।
- राव, के., एवं मेहता, ए. (2019). IT-ITES प्रशिक्षण और महिला रोजगार का क्षेत्रीय विश्लेषण। *तकनीकी शिक्षा समीक्षा*, 11(2), 88-102।
- रहमान, टी. (2023). JSLPS आधारित कौशल प्रशिक्षण का महिला निर्णय-क्षमता पर प्रभाव। *सामुदायिक विकास शोध पत्रिका*, 10(1), 44-57।
- शेट्टी, पी., एवं वर्मा, डी. (2025). कौशल प्रशिक्षण और महिला आर्थिक एजेंसी: एक आधुनिक विश्लेषण। *नारी शक्ति शोध जर्नल*, 4(1), 1-14।
- संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women). (2023). *महिला आर्थिक सशक्तिकरण: वैश्विक प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2022). *दक्षिण एशिया में कौशल विकास और लैंगिक समानता*. न्यूयॉर्क: यूएनडीपी।
- झारखंड सरकार. (2023). *झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23*. रांची: वित्त विभाग, झारखंड शासन।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). (2023). *श्रम-बल भागीदारी सर्वेक्षण रिपोर्ट*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE). (2022). *स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- NSDC. (2023). *भारत में महिला कौशल विकास और रोजगार सहभागिता रिपोर्ट*. नई दिल्ली: NSDC प्रकाशन।
- JSLPS. (2023). *वार्षिक प्रगति रिपोर्ट*. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, रांची।
- Asian Development Bank. (2022). *Tribal Women's Livelihood and Skill Gaps* (हिंदी अनुवाद) । मनीला: ADB प्रकाशन।
- इंडिया टुडे. (2023). झारखंड में महिलाओं की उद्यमिता और कौशल-विकास पहल। *इंडिया टुडे ऑनलाइन*. https://www.indiatoday.in
- प्रभात खबर. (2023). झारखंड की महिलाओं में कौशल प्रशिक्षण से बढ़ती आर्थिक भागीदारी। https://www.prabhatkhabar.com